NITIN SIR CLASSES

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 08 Oct, 2025

Edition : InternationalTable of Contents

Page 01 Syllabus : GS 3 : Science and Technology / Prelims	'क्वांटम टनलिंग' को प्रदर्शित करने वाले उपकरण के निर्माण के लिए ट्रायो को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला
Page 06 Syllabus : GS 2 : Governance/ Prelims	'किसी भी राज्य ने प्रमुख दवा गुणवत्ता मानदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है'
Page 07 Syllabus : Prelims	सुपरमून क्या है?
Page 09 Syllabus : GS 7 : Internal Security / Prelims	माओवादियों के लिए हथियार डालने का समय आ गया है
Page 10 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	भारतीय पूंजी को घरेलू निवेश की आवश्यकता क्यों है
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 3 : Indian Economy	प्रगति का एक ऐसा मार्ग जो सोने से पक्का है

Page 01 : GS 3 : Science and Technology/ Prelims

2025 का **भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** तीन वैज्ञानिकों — **जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट** और **जॉन मार्टिनिस** — को दिया गया है। इन वैज्ञानिकों ने **क्वांटम टनलिंग (Quantum Tunnelling)** नामक अद्भुत घटना को समझने और प्रदर्शित करने के लिए एक **विद्युत परिपथ (Electrical Circuit)** विकसित किया। यह उपलब्धि **क्वांटम यांत्रिकी (Quantum Mechanics)** के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य के **क्वांटम कंप्यूटरों और डिजिटल तकनीकों** की आधारशिला बनेगा।

Trio wins the Physics Nobel prize for building device that demonstrates 'quantum tunnelling'

Jacob Koshy
NEW DELHI

The Nobel Prize for Physics this year will be awarded to three scientists – John Clarke, Michel Devoret and John Martinis, the Royal Swedish Academy of Sciences said on Tuesday. The three worked together and devised experiments to tease greater insight into the workings of the quantum world: the realm of the ultra-small when objects, broken down to single, constituent particles, cease to behave in the way we ordinarily expect them to.

One of the mind-boggling behaviours that particles are capable of here is "tunnelling", literally, the ability of particles to pass through physical walls.

It is as if a cricket ball hitting the pitch will surely bounce up, but the odd cricket-ball particle will simply burrow into the ground.

Such strange behaviour cannot be observed at the macroscopic level but these scientists showed that it was possible to organise a multitude of single particles and coerce them to exhibit "tunnelling" properties.

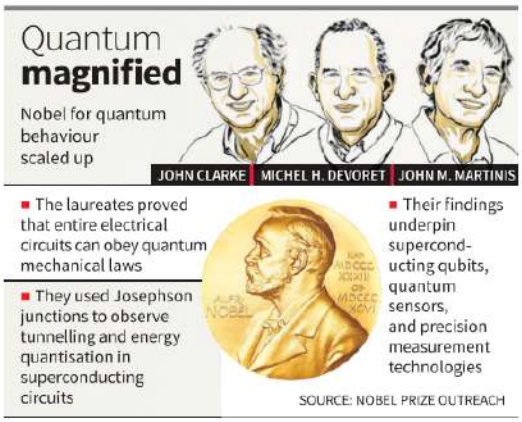

Electrical circuit

Much like early insight into quantum mechanics paved the way for transistors and silicon chips in the 1950s, the three scientists devised an electrical circuit with two superconductors, components that can conduct a current without any electrical resistance.

They separated these with a thin layer of material – called a Josephson junction – that did not conduct any current at all.

In this experiment, they showed that they could control and investigate a phenomenon in which all the charged particles in the superconductor behave in unison, as if they are a single 'particle' that fills the entire circuit. Following this, they were able to demonstrate that such a particle could be made to behave simulating the flow of electricity even without voltage, a prerequisite for the flow of current.

"It is wonderful to be able to celebrate the way that century-old quantum mechanics continually offers new surprises. It is also enormously useful, as quantum mechanics is the foundation of all digital technology," said Olle Eriksson, Chair of the Nobel Committee for Physics.

EDITORIAL ON
» PAGE 8

क्वांटम टनलिंग क्या है?

- **क्वांटम टनलिंग** वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कण (particle) उस बाधा (barrier) को पार कर जाता है जिसे वह **सामान्य भौतिकी (Classical Physics)** के अनुसार पार नहीं कर सकता।
- उदाहरण के लिए, जैसे एक गेंद दीवार से नहीं गुजर सकती, वैसे ही सूक्ष्म स्तर पर कोई इलेक्ट्रॉन दीवार जैसी ऊर्जा बाधा को पार कर सकता है।

- यह घटना तार्किक रूप से अकल्पनीय है, परंतु **क्वांटम सिद्धांतों** में यह संभव है क्योंकि वहाँ कणों का व्यवहार **संभाव्यता (Probability)** पर आधारित होता है।

वैज्ञानिकों का प्रयोग (The Nobel-winning Work)

- इन वैज्ञानिकों ने दो **सुपरकंडक्टरों (Superconductors)** को एक **अचालक परत (Insulating Layer)** से अलग करके एक **Josephson Junction** बनाया।
- इस परिपथ में उन्होंने दिखाया कि कैसे सभी आवेशित कण (चार्ज पार्टिकल्स) एक साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे **एक ही कण** हों।
- उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि इस प्रणाली में **बिना वोल्टेज लगाए भी विद्युत प्रवाह (Current Flow)** उत्पन्न किया जा सकता है — जो क्वांटम टनलिंग का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

स्थैतिक संदर्भ (Static Linkages)

1. **क्वांटम यांत्रिकी:**20वीं सदी के प्रारंभ में **प्लैंक, आइंस्टीन, बोहर, हाइजेनबर्ग** आदि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सिद्धांत।
2. **Josephson Junction:**1962 में **ब्रायन जोसेफसन** ने प्रस्तावित किया (1973 में नोबेल पुरस्कार)। इसका उपयोग **SQUIDs** और **क्वांटम सर्किट्स** में होता है।
3. **सुपरकंडक्टिविटी:**1911 में **हेइके कैमरलिंग ओनेस** ने खोजी थी — इसमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

- यह खोज आधुनिक **क्वांटम तकनीकों** — जैसे **क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार** और **क्वांटम सेंसरिंग** — के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत ने 2023 में **राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission - NQM)** शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2031 तक **क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम नेटवर्क** और **क्वांटम सिमुलेटर** तैयार करना है।
- नोबेल विजेताओं का यह कार्य **क्वांटम बिट्स (Qubits)** को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

महत्त्व (Significance)

- **वैज्ञानिक दृष्टि से:** यह प्रयोग क्वांटम स्तर के रहस्यमय व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करता है।
- **प्रौद्योगिकीय दृष्टि से:** यह **क्वांटम कंप्यूटर**, **सुरक्षित संचार प्रणाली** और **उन्नत माइक्रोचिप्स** के लिए आधार तैयार करता है।
- **आर्थिक दृष्टि से:** यह "क्वांटम अर्थव्यवस्था" की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आने वाले दशकों में तकनीकी क्रांति का केंद्र बनेगा।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह नोबेल पुरस्कार यह सिद्ध करता है कि **क्वांटम यांत्रिकी** अभी भी नये चमत्कारों से भरा हुआ क्षेत्र है। जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरेट और जॉन मार्टिनिस का कार्य **सैद्धांतिक भौतिकी** और **व्यावहारिक तकनीकी विकास** के बीच सेतु का कार्य करता है। यह खोज न केवल विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, बल्कि आने वाले **क्वांटम युग (Quantum Age)** की नींव भी रखती है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन "क्वांटम टनलिंग" के बारे में सही है?

1. यह केवल उच्च तापमान पर ही संभव है।

2. यह घटना शास्त्रीय भौतिकी से नहीं समझाई जा सकती।

3. इसका उपयोग क्वांटम कंप्यूटरों में किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए –

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) सभी सही हैं

Ans : b)

UPSC Mains Practice Question

Ques: क्वांटम तकनीकों के तीव्र विकास से जुड़े वैज्ञानिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। **(250 Words)**

Page 06 : GS 2 : Governance / Prelims

भारत विश्व की "**फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड**" कहलाता है, क्योंकि यहाँ की दवाएँ सस्ती और सुलभ हैं।लेकिन हाल ही में **मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु** जैसी घटनाओं ने भारत की **दवा गुणवत्ता निगरानी प्रणाली** पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, **18 राज्यीय औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों** ने यद्यपि **ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS)** अपनाया है, परंतु **Corrective and Preventive Action (CAPA)** दिशानिर्देशों का **कोई भी राज्य पूर्ण पालन नहीं कर पाया है**। दोनों ही प्रावधान केंद्र सरकार की संशोधित **अनुसूची M (Schedule M)** का हिस्सा हैं।

पृष्ठभूमि: अनुसूची M और संशोधित GMP मानक

- **अनुसूची M** भारत में **Good Manufacturing Practices (GMP)** के मानकों को परिभाषित करती है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औषधियाँ **समान गुणवत्ता** और **सुरक्षित परिस्थितियों** में निर्मित हों।
- 2023 में सरकार ने अनुसूची M को संशोधित किया ताकि **दवा निर्माण की पारदर्शिता और गुणवत्ता नियंत्रण** को और सशक्त बनाया जा सके, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने आए **दूषित दवाओं के मामलों** के बाद।

मुख्य तत्व: CAPA और ONDLS

1. Corrective and Preventive Action (CAPA):

'No State has fully complied with key drug quality norms'

Bindu Shajan Perappadan
NEW DELHI

CAPA guidelines form a critical part of Centre's revised pharmaceutical manufacturing regulations

While 18 State drug control authorities across the country have adopted the Online National Drugs Licensing System (ONDLS) for processing drug-related licences, no State has yet fully complied with the Corrective and Preventive Action (CAPA) guidelines, confirmed a source in the Union Health Ministry.

Both the ONDLS and CAPA are provisions under the Central government's revised Schedule M, which is a critical update to India's pharmaceutical manufacturing regulations.

Safety standards

"CAPA is crucial for ensuring safety and maintaining high standards in regulated industries such as pharmaceuticals. It is a universal quality management methodology for process improvement," the official said.

Voluntary compliance [with CAPA] is crucial for quality maintenance, he said, while speaking about the recent deaths of children in Madhya Pradesh and Rajasthan due to consumption of adulterated cough syrup.

CAPA also focuses on systematically investigating and resolving problems in managment issues. "Compliance with CAPA will ensure that drug violation is registered and corrective action is taken," the official said.

The ONDLS is a digital, single-window platform for processing various drug-related licences in India and has been developed by the Centre for Development of Advanced Computing in coordination with the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO).

"The system is designed to create a uniform, transparent, and accountable process for drug licensing across all States and Union Territories. It handles applications for manufacturing and sales licences, blood banks, and various certificates, such as WHO-GMP," said the official.

Data shared with *The Hindu* show that of the total 5,308 MSME pharma companiesin India, 3,838 have already complied with the revised Schedule M GMP.

- यह एक **गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली** है जो निर्माण प्रक्रिया में हुई गलती या त्रुटि के मूल कारणों की पहचान कर उन्हें सुधारने और रोकने पर केंद्रित है।
- CAPA के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी **गुणवत्ता उल्लंघन** का समाधान और भविष्य में उसकी **पुनरावृत्ति न हो**।
- परंतु वर्तमान में **किसी भी राज्य ने पूर्ण CAPA अनुपालन नहीं किया है**, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

2. Online National Drugs Licensing System (ONDLS):

- यह **एकल डिजिटल मंच** है जिसे **सी-डैक (C-DAC)** और **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** ने विकसित किया है।
- इसका उद्देश्य है—दवा निर्माण, बिक्री, रक्त बैंक और WHO-GMP प्रमाणपत्र जैसी **सभी लाइसेंस प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना**।
- अब तक **18 राज्यों** ने इस प्रणाली को अपनाया है।

वर्तमान स्थिति

- भारत में कुल **5,308 MSME फार्मा कंपनियाँ** हैं, जिनमें से **3,838** ने संशोधित **Schedule M GMP** का पालन किया है।
- परंतु **CAPA का पूर्ण अनुपालन** किसी राज्य में नहीं हुआ है।
- दूषित कफ सिरप की घटनाएँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि **गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी में गंभीर खामियाँ** हैं।

UPSC स्थैतिक संदर्भ

1. **CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization):**दवा गुणवत्ता नियंत्रण और अनुमोदन के लिए भारत की सर्वोच्च नियामक संस्था।
2. **GMP (Good Manufacturing Practice):**WHO द्वारा निर्धारित मानक जिससे यह सुनिश्चित होता है कि औषधियाँ **सुरक्षित, शुद्ध और प्रभावी** हों।
3. **संघ–राज्य जिम्मेदारी:**दवा निर्माण का **मानक निर्धारण केंद्र का कार्य**, जबकि **लाइसेंस जारी करना और निरीक्षण करना राज्यों का कार्य** है।

महत्त्व और चुनौतियाँ

महत्त्व:

- दवाओं की **गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा** सुनिश्चित होती है।
- डिजिटल प्रक्रिया से **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** बढ़ता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानकों** के अनुरूप उत्पादन से भारत की **वैश्विक साख मजबूत** होती है।

चुनौतियाँ:

- **राज्यों में एकरूप अनुपालन की कमी**।
- **प्रशिक्षित औषधि निरीक्षकों की कमी**।
- **CAPA दिशानिर्देशों की कमजोर निगरानी**।

- राज्य स्तर पर **तकनीकी एवं डिजिटल अवसंरचना की कमी**।

आगे की राह (Way Forward)

- **CDSCO और राज्यों के बीच समन्वय** को सुदृढ़ किया जाए।
- निरीक्षकों और MSME फार्मा इकाइयों को **CAPA प्रशिक्षण** दिया जाए।
- सभी राज्यों में **ONDLS का अनिवार्य कार्यान्वयन** हो।
- **नियमित ऑडिट और मूल्यांकन** प्रणाली लागू की जाए।
- **Pharma Vision 2047** के तहत राष्ट्रीय GMP अनुपालन कार्यक्रम को गति दी जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की फार्मा सफलता केवल **सस्ती दवाओं** पर नहीं, बल्कि **गुणवत्ता और सुरक्षा** पर भी निर्भर करती है।CAPA के अधूरे अनुपालन से यह स्पष्ट है कि **नीति और क्रियान्वयन के बीच अंतर** अब भी मौजूद है।यदि भारत को वास्तव में "**विश्व की फार्मेसी**" बने रहना है, तो उसे **एकरूप, पारदर्शी और सशक्त दवा गुणवत्ता प्रणाली** अपनानी ही होगी।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

1. Corrective and Preventive Action (CAPA) प्रणाली दवा गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित है।

2. Online National Drugs Licensing System (ONDLS) को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने विकसित किया है।

3. अनुसूची M (Schedule M) भारत में औषधियों की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से संबंधित है।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3

(D) 1, 2 और 3

Ans: (a)

UPSC Mains Practice Question

Ques: भारत को "विश्व की फार्मेसी" के रूप में अपनी साख बनाए रखने के लिए औषधि गुणवत्ता नियमन में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? CAPA और ONDLS जैसे हालिया सुधार इस दिशा में कैसे सहायक सिद्ध हो सकते हैं? (**150 Words)**

Page 07 : Prelims

सुपरमून वह खगोलीय घटना है जब **पूर्णिमा** या **अमावस्या** का चंद्रमा अपनी **पृथ्वी से न्यूनतम दूरी (परिजी)** पर होता है। इस स्थिति में चंद्रमा सामान्य से **लगभग 14% बड़ा** और **30% अधिक चमकीला** दिखाई देता है। "सुपरमून" शब्द को सबसे पहले **ज्योतिषी रिचर्ड नोल (Richard Nolle)** ने 1970 के दशक में प्रचलित किया था, जिसे अब वैज्ञानिक और मीडिया दोनों उपयोग करते हैं।

Static Context

- चंद्रमा की कक्षा **अंडाकार (elliptical)** होती है, जिसके कारण उसकी पृथ्वी से दूरी लगभग **50,000 किलोमीटर** तक बदलती रहती है।
- **परिजी (Perigee)** पर चंद्रमा लगभग **3,63,000 किमी** की दूरी पर होता है, जबकि **अपोजी (Apogee)** पर यह लगभग **4,05,000 किमी** दूर होता है।
- जब पूर्णिमा पर चंद्रमा परिजी के निकट होता है, तो यह अपेक्षाकृत **बड़ा और अधिक उज्ज्वल** दिखाई देता है।
- यह अंतर आँखों से बहुत स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन क्षितिज के पास चंद्रमा अधिक भव्य प्रतीत होता है।

WHAT IS IT?

What is a supermoon?

Vasudevan Mukunth

A supermoon occurs when a full moon or new moon coincides with the moon's closest approach to the earth in its elliptical orbit — a point known as the perigee. Because the moon's orbit is not a perfect circle, its distance from the earth varies throughout the month by around 50,000 km. When the moon is near its perigee and also directly opposite the sun, the full moon appears about 14% larger and 30% brighter than when it is at its farthest point. This is the supermoon.

A supermoon was visible on the night of October 7 and will appear twice more in November and December.

The astrologer Richard Nolle popularised the term 'supermoon' in the 1970s, but it has since been adopted by astronomers and the media to describe the visually striking lunar events. Though the difference in size is subtle to the naked eye, the enhanced brightness often makes the moon appear vivid against the night sky, especially when seen low on the horizon.

Supermoons also influence the tides, creating perigean spring tides. These tides are slightly higher and lower than usual because the moon's stronger gravitational pull acts in concert with that of the sun. While the changes are typically modest, they can exacerbate coastal flooding when combined with storm surges.

Culturally, supermoons have long captured human imagination, inspiring folklore and spiritual observances across civilisations. They also offer opportunities for astronomers and photographers to observe lunar surface details and study tidal effects more clearly.

A full moon sets behind Stonehenge in April 2021, in Amesbury, England. GETTY IMAGES

For feedback and suggestions
for 'Science', please write to
science@thehindu.co.in
with the subject 'Daily page'

Daily News Analysis

Current Contex:

- **7 अक्टूबर 2025** की रात को सुपरमून दिखाई दिया और **नवंबर व दिसंबर 2025** में दो बार और दिखाई देगा।
- इस समय वैज्ञानिक इसके माध्यम से **चंद्र सतह का अवलोकन**, **ज्वारीय प्रभावों** का अध्ययन और **जनसंपर्क कार्यक्रम** आयोजित करते हैं।
- सुपरमून के समय **परिजीय ज्वार (Perigean Spring Tides)** उत्पन्न होते हैं, जिनमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के साथ मिलकर **ऊँचे और नीचले ज्वार** को थोड़ा और तीव्र बना देता है। कभी-कभी यह **तटीय बाढ़** को भी बढ़ा सकता है।

सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व:

- विभिन्न सभ्यताओं में सुपरमून को **धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि** से विशेष महत्व दिया गया है।
- यह घटना **खगोल विज्ञान के प्रति जन-जागरूकता** बढ़ाने और **वैज्ञानिक अध्ययन** के लिए भी उपयोगी होती है।

निष्कर्ष:

सुपरमून केवल एक आकर्षक खगोलीय दृश्य नहीं, बल्कि यह **पृथ्वी-चंद्रमा तंत्र की गतिशीलता** का उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि इसका पृथ्वी पर भौतिक प्रभाव सीमित होता है, फिर भी यह **वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से** अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो **प्रकृति और मानव कल्पना** को जोड़ती है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: सुपरमून के दौरान उत्पन्न "परिजीय वसंत ज्वार (Perigean Spring Tides)" का कारण है—

A. चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों का संयुक्त प्रभाव

B. पृथ्वी के घूर्णन की गति में कमी

C. समुद्र की लवणता में वृद्धि

D. चंद्रग्रहण का प्रभाव

Ans: a)

Page09: GS 3 : Internal Security / Prelims

माओवादी आंदोलन, जिसे नक्सलवाद भी कहा जाता है, भारत की सबसे लंबे समय से चली आ रही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक रहा है। यह आंदोलन 1960 के दशक के अंत में भूमि और ग्रामीण असमानताओं के खिलाफ उभरा था। मूल रूप से पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में किसान-नेतृत्व वाले संघर्ष के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन अब व्यापक रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, बिहार और महाराष्ट्र में फैल चुका है। वर्षों में यह संगठनात्मक रूप से मजबूत होकर **सीपीआई (माओवादी)** बन गया और जंगलों में 'मुक्त क्षेत्र' स्थापित किए। सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए **सुरक्षा उपाय, विकास कार्यक्रम और समर्पण-पुनर्वास नीति** अपनाई है।

Daily News Analysis

It's time for Maoists to lay down arms

Recently, Union Home Minister Amit Shah ruled out talks with the Maoists and said that they will have to lay down weapons by accepting the government's "lucrative surrender and rehabilitation policy". Reiterating that the government was firm about eradicating Maoism by next year, he asked the Maoists to surrender and join the mainstream.

It is time for the Maoists to seriously consider this offer. In the last two decades, the highest decision-making bodies of the proscribed Communist Party of India (Maoist) – the Central Committee and the Politburo – have shrunk drastically in both size and influence. In 2004, when the CPI (Marxist-Leninist) People's War Group and the Maoist Communist Centre merged to form the CPI (Maoist), there were about 42 Central Committee members, who were young intellectuals, and 10,000 cadre. Today, the Central Committee has just 13 members. Nearly all of them are over 60, fatigued, and suffer illnesses. The cadre base has reduced to below 2,000. The Politburo has shrunk from about 25 to merely 7-8 members.

It is clear that the armed rebellion has reached a dead end, and the movement, already in decline for some time, is now at its weakest. Even in their traditional stronghold in Chhattisgarh, once declared a 'Liberated Zone', the Maoist influence has waned.

Sumit Bhattacharjee

The beginning of the decline

For a long time, the Maoists ruled the roost in the underdeveloped and tribal districts of combined Andhra Pradesh, Odisha, and Chhattisgarh. When Andhra Pradesh and Odisha augmented their police forces with specialised forces, the Maoists were slowly pushed into Chhattisgarh. In that forested State, they held sway for more than two decades. The 'Liberated Zone' also became a reality, as the Maoists ran a parallel government, which they called 'Janatana Sarkar'. Their control spread over Sukma, Dantewada, Bijapur, Narayanpur, Kanker, Rajnandgaon and Bastar.

However, the introduction of the Commando Battalion for Resolute Action, a specialised unit of the Central Reserve Police Force trained in jungle warfare and guerrilla tactics, began to change things. The deployment of the District Reserve Guard (DRG) – a counterinsurgency force comprising surrendered Maoists and former members of the disbanded Salwa Judum, which was raised by the Chhattisgarh government – also proved to be a game changer. The DRG played a crucial role in Operation Black Forest, a mission that destroyed a major Maoist stronghold and the Maoists' headquarters in the Karregutta hills. In the beginning of 2025, there were about 20 Central Committee members. Between January and June, the DRG killed five of them, including general secretary Nambala Keshava Rao alias Basavaraju.

Apart from this, in the last 18 months, security forces have also killed more than 430 Maoists, including Central Committee members, mid-level leaders, and cadres, including about 45 women operatives. Over 1,450 Maoists have surrendered and about 1,460 have been arrested. All these setbacks have substantially reduced the movement's military strength and reduced the Maoists' intellectual and political base.

It is clear that the movement, already in decline for some time, is now at its weakest

A crisis of leadership

The biggest crisis confronting the Maoists is of leadership. The killing of Basavaraju brought the movement's tensions to the forefront. While nearly the entire military force comprises tribal people, especially Gonds, a dominant tribal group in Chhattisgarh, leaders of the movement have always been upper caste, primarily from Andhra Pradesh and Telangana. It was only when tensions came to the surface that the top leadership chose Telagana-based Dalit leader, Tippiri Tirupathi alias Debuji, as the new general secretary. Now, 10 Central Committee members are from Andhra Pradesh and Telangana, three from Jharkhand, and two from Chhattisgarh.

Chhattisgarh has always presented a unique case in the Maoist insurgency. Unlike West Bengal, Andhra Pradesh, or Bihar – where the movement originated and thrived as a peasant-led struggle rooted in land issues and supported by intellectuals – Chhattisgarh was not the birthplace of the movement. Instead, it was chosen by Maoists as a strategic safe haven after they were pushed out of Andhra Pradesh and Bengal. Many of the tribal people in Chhattisgarh, who have surrendered, say that they joined the movement motivated by the songs and plays enacted by the cultural wing of the Maoists and not because of ideology.

Ironically, the state-sponsored Salwa Judum movement became a blessing in disguise for the Maoists. The atrocities committed by Judum members against tribal groups drove many tribal people into the Maoist fold. However, as both sides engaged in violence, the tribal people increasingly found themselves caught in the crossfire. This led to growing disillusionment and a gradual distancing of tribal communities from the Maoist movement.

The Maoists' preference for militarisation over political development has hit the movement hard. Over the past 25 years, there has been a sharp decline in their intellectual base, overground support, and recruitment of educated youth. Combined with the modernisation of security forces, improved intelligence-sharing, and coordinated operations, this has pushed the Maoists into a corner.

This decline shows that a sustained people's movement with the backing of the civil society in a democratic way would have yielded better results than an armed struggle, such as what happened in Niyamgiri in Odisha or Sompeta in Andhra Pradesh.

sumit.b@thehindu.co.in

वर्तमान संदर्भ और विश्लेषण:

1. **माओवादी ताकत में गिरावट:**
   - केंद्रीय समिति 42 से घटकर **13 सदस्य** और पोलितब्यूरो 25 से घटकर **7–8 सदस्य** रह गया।
   - कैडर संख्या 10,000 से घटकर **2,000 से कम**।
   - वरिष्ठ और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नेता आंदोलन की **नेतृत्व और संगठनात्मक कमजोरी** दर्शाते हैं।
2. **सुरक्षा ऑपरेशनों की भूमिका:**
   - **कोब्रास (CoBRA)** और **डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG)** ने माओवादियों को कमजोर किया।
   - ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में माओवादी मुख्यालय और नेता मारे गए।
   - हाल के वर्षों में **430+ माओवादी मारे गए, 1,450+ समर्पण**, जिससे सैन्य ताकत और बौद्धिक आधार कम हुआ।
3. **नेतृत्व संकट और जातीय तनाव:**
   - शीर्ष नेतृत्व **अपर जाति (आंध्र/तेलंगाना)** का है, जबकि सैनिक ज्यादातर **छत्तीसगढ़ के आदिवासी (गोंड)**।

- हाल ही में तेलंगाना के दलित नेता **तिप्पिरी तिरुपति** को महासचिव बनाया गया।
- आदिवासी समुदाय अब हिंसा और निराशा के कारण माओवादी आंदोलन से दूरी बना रहे हैं।

4. **सैन्य रणनीति बनाम राजनीतिक विकास:**
   - सैन्यरण के प्रति प्राथमिकता ने **बौद्धिक और युवाओं के समर्थन में गिरावट** ला दी।
   - आदिवासी आंदोलन (जैसे नीयमगिरी, सोमपेटा) दिखाते हैं कि **लोकतांत्रिक और विकास आधारित आंदोलन** अधिक प्रभावी होते हैं।
5. **सरकार की रणनीति:**
   - गृह मंत्री अमित शाह का संदेश: माओवादी **समर्पण और पुनर्वास नीति** के जरिए मुख्यधारा में लौट सकते हैं।
   - यह **हार्ड पावर (सुरक्षा) और सॉफ्ट पावर (विकास/समर्पण)** का संयोजन है।

Static Context

- **नक्सलवाद/माओवादी:** माओवादी विचारधारा पर आधारित वामपंथी चरमपंथी आंदोलन।
- **मुख्य प्रभावित क्षेत्र:** रेड कॉरिडोर – छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश।
- **सुरक्षा बल:** CoBRA, ग्रेहाउंड्स (AP), DRG (छत्तीसगढ़)।
- **सरकारी उपाय:** समर्पण-पुनर्वास योजना, विकास पहलें, समन्वित सुरक्षा ऑपरेशन।
- **कानूनी उपाय:** UAPA, 2009 में CPI (Maoist) पर प्रतिबंध।

निष्कर्ष:

भारत में माओवादी आंदोलन, जो कभी शक्तिशाली सशस्त्र विद्रोह था, अब **नेतृत्व संकट, घटती कैडर संख्या, सुरक्षा ऑपरेशन और आदिवासी समर्थन की कमी** के कारण कमजोर हो चुका है। सरकार की **हार्ड और सॉफ्ट पावर रणनीति**—सुरक्षा उपायों के साथ समर्पण और पुनर्वास—माओवादी को मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रस्तुत करती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि **लंबे संघर्ष की तुलना में लोगों-केंद्रित लोकतांत्रिक और विकास आधारित रणनीति अधिक प्रभावी है।**

UPSC Prelims Practice Question

Ques : "Janatana Sarkar" किसका परिचायक था?

A) भारतीय कांग्रेस का लोक प्रशासन

B) माओवादी आंदोलन का parallel प्रशासन

C) झारखंड सरकार का प्रशासन

D) राज्य सरकार का पंचायत मॉडल

Ans: B)

UPSC Mains Practice Question

Ques : माओवादी आंदोलन में आदिवासी समुदायों की भूमिका और उनका बदलता दृष्टिकोण कैसे इस आंदोलन की ताकत और कमजोरियों को प्रभावित करता है? **(150 Words)**

Page 10 : GS 3: Indian Economy/ Prelims

Daily News Analysis

वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में बढ़ते **शुल्क, व्यापारिक युद्ध और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता** जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत के लिए, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, यह स्थिति **जोखिम और अवसर दोनों** प्रस्तुत करती है। ऐसे समय में **घरेलू पूंजी** का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है ताकि विकास की गति बनी रहे, रोजगार और आय में असमानता कम हो, और घरेलू मांग को बढ़ावा मिले। अब भारतीय व्यापारिक घरानों से अपेक्षा है कि वे केवल लाभ अर्जित करने के बजाय **राष्ट्रीय हितों के साथ तालमेल** बनाएँ।

Why Indian capital needs to invest domestically

As the global economy now moves to an extended period of uncertainty, due to tariffs and fluctuations in world trade, India's private business houses have to work closely with the government and align with public interest to maintain the economy's growth momentum

ECONOMIC NOTES

M. Suresh Babu

A central challenge for policy makers in India, at the present juncture, is to work out a balance between the long-term benefits of global trade and the short-term harms that current uncertainties pose to large sections of the population who are at risk of low wages and unemployment. Tackling this requires a change of the existing system to account for the needs of the larger masses rather than only enriching private capital's interests.

The evolution of capital

Indian capital has an important role to play in this change by becoming more inclusive of a broader set of interests beyond individual profits and rapid accumulation. The history of capitalism shows that this is not impossible as capitalism has evolved before, and if it is to continue into the future, it can evolve again. As the economy is at risk of negative shock to external demand for its products, due to unprecedented tariffs imposed and distortions caused in the global trading system, Indian capital needs to reinvent itself and work closely with the government to mitigate the risks posed.

Historically private businesses, managed by Indian capital, have clamoured for a more active role in the economy as well as larger concessions and subsidies along with a liberal business environment. Governments have often been called on to command and control such businesses. These private enterprises used India's protected economic environment (pre-liberalisation) to grow and accumulate by riding on inward-looking policies and reaping supernormal profits (excess of normal profit) from protected domestic markets. The accumulated surpluses gave them the confidence to cross borders, buy out businesses elsewhere and forge global links when the economy opened up in the early nineties. This phenomenon, though not widespread among Indian businesses, has created depth in Indian capital, spawning some giants who control various important sectors of Indian industry.

However, as the global economy now moves to an extended period of uncertainty, these business houses now have to work closely with the government and align with public interest to maintain the economy's growth momentum.

Three key processes were instrumental in the emergence and subsequent development of mass markets in the contemporary global economy. First, the creation of a wage-labour class; second, the productivity-enhancing effects of industrial mass production; and third, changes in the composition of demand as personal incomes grew.

The growth of demand is an important but unrecognised ingredient in these processes. Firms require an expansion of demand if they are to realise profits from the production of additional goods and services. Most of the current macroeconomic policy frameworks simply assume that demand responds passively to supply, therefore the expansion of the latter is all that is of interest to growth.

In a globalised world, demand has two components, domestic and external. Early approaches to industrialisation focussed on the domestic component and later ones emphasised on the external side. The current turbulence in the global economy has led to shocks in external demand and hence exports are impacting aggregate demand and inducing vulnerabilities and fluctuations in external demand. In this scenario turning to domestic markets, raising the levels of domestic demand and catering to it, remains a viable option.

ISTOCKPHOTO

The importance of domestic capital

In India, domestic capital has an important role to play in stimulating domestic demand via three routes.

The first area for more active involvement of Indian capital is to enhance internal private investments. Despite India Inc. sitting on record-high profits, the willingness to invest hasn't kept pace with such profits. During the post-COVID period, public investments did all the heavy lifting. Fiscal policy has been fine-tuned to offer incentives, while monetary policy has been responding with easier access to credit. A bulk of the regulatory requirements have been simplified along with the tax regime. Infrastructure development has been accorded high priority along with a slew of benefits, such as production-linked incentives. The net effect of all these is reflected in the indicators of the business environment.

However, despite these efforts by the government, private investments have remained flat over the past few years. The Finance Ministry in its June monthly review noted that "Slow credit growth and private investment appetite may restrict acceleration in economic momentum," underscoring the urgent need for the private sector to step up.

While private capex remains subdued, public capital expenditure surged from ₹3.4 lakh crore in FY20 to ₹10.2 lakh crore in FY25, which is a compound annual growth rate (CAGR) of 25%, driven largely by railways, roads, highways, and communications. Interestingly, during a period of sluggish domestic private investments, India's outward foreign direct investment (FDI) flows have grown at a sharp pace over the past five years, with a CAGR of 12.6%, much higher than the global average of 3.9%. This indicates that Indian capital is keener to explore foreign locations than its domestic economy. An opportune time has come for a reversal of this.

The second thrust area is to ensure that there is moderate wage growth in the economy. The Economic Survey 2024-25 flagged the trend of increasing corporate profits and lagging wage growth. In 2023-24, profits touched a 15-year high, while growth in wages stagnated. This affects distribution in the economy and dampens domestic demand. Rating agencies project that real wage growth might decline to 6.5% in FY26, down from 7% in FY25. Real wages are expected to grow faster when inflation is low. However, we find evidence contrary to it indicating worsening of distribution. The growing trend towards contractualisation within formal sectors has been eroding the collective bargaining power of workers, leading to slower wage growth within the manufacturing sector.

The third area for priority action is to invest more in Research and Development (R&D). The tendency has been to invest less and only in areas of quick returns. This paradigm has to change as fundamental research and development is crucial for long-term productivity gains. The gross expenditure on R&D in India is 0.64% of the GDP, which is insufficient and remains low compared to many advanced economies. Further, R&D funding in India is primarily through the government. In the U.S., China, Japan, and South Korea, private enterprises routinely contribute more than 70% to the total national R&D expenditure. In China, R&D spending has reached 2.4% of the GDP, with the private sector complementing the funding of the government, while in India only around 36% of R&D is funded by the private sector. In India not only is the private sector investment in innovation low, but it is also concentrated in sectors such as drugs and pharmaceuticals, information technology, transport, defence, and biotechnology.

The road ahead

An uncertain global economic environment calls for unified responses from the government and the private sector.

While the government has been facilitating the creation of a favourable environment for businesses, that effort alone is not sufficient for tackling present challenges. Long-term national interest needs to be protected by Indian capital by keeping it as an objective above profit maximisation. It is time for Indian capital to step in more actively.

M Suresh Babu is Director, Madras Institute of Development Studies. The views expressed are personal.

THE GIST

- At the economy is at risk of negative shock to external demand for its products, due to unprecedented tariffs imposed and distortions caused in the global trading system, Indian capital needs to reinvent itself and work closely with the government to mitigate the risks posed.
- The first area for more active involvement of Indian capital is to enhance internal private investments. Despite India Inc. sitting on record-high profits, the willingness to invest hasn't kept pace with such profits.
- While the government has been facilitating the creation of a favourable environment for businesses, that effort alone is not sufficient for tackling present challenges.

Static Context

Daily News Analysis

1. **भारतीय पूंजी का ऐतिहासिक विकास**
   - उदारीकरण से पहले, भारतीय व्यवसाय **संरक्षित आर्थिक वातावरण** का लाभ उठाकर बढ़े और सुपरनॉर्मल मुनाफ़ा अर्जित किया।
   - 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर विस्तार करने लगीं।
   - इससे कुछ उद्योग समूह प्रमुख बने, जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, आईटी और फार्मास्यूटिकल्स।
2. **पूंजीवाद और घरेलू मांग**
   - आर्थिक विकास के तीन आधार हैं: **मजदूर वर्ग का निर्माण, औद्योगिक उत्पादन, और व्यक्तिगत आय में वृद्धि**।
   - उत्पादन तभी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है जब **मांग मौजूद हो**।
   - वर्तमान में भारत में घरेलू मांग का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, जबकि निजी निवेश अपेक्षाकृत धीमा है।
3. **निजी निवेश प्रवृत्ति**
   - पोस्ट-COVID, **सार्वजनिक निवेश** बढ़ा (FY20 ₹3.4 लाख करोड़ → FY25 ₹10.2 लाख करोड़; CAGR 25%)।
   - निजी निवेश स्थिर रहा, जबकि **विदेश में निवेश (FDI)** तेज़ी से बढ़ा (CAGR 12.6%)।
   - **मुनाफ़े बढ़ने के बावजूद मजदूरी वृद्धि धीमी** रही, जिससे घरेलू मांग पर असर पड़ा।
4. **अनुसंधान और विकास (R&D) में कमी**
   - भारत का R&D व्यय **GDP का 0.64%**, जिसमें केवल 36% निजी क्षेत्र द्वारा।
   - अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में निजी क्षेत्र R&D का **70% से अधिक योगदान** देता है।

वर्तमान संदर्भ

1. **वैश्विक अस्थिरता**
   - शुल्क और व्यापार असंतुलन के कारण **निर्यात पर निर्भरता वाली अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित** हो रही हैं।
   - भारत में **घरेलू मांग को बढ़ाना और निवेश को प्रोत्साहित करना** आवश्यक है।
2. **नीतिगत पहल**
   - सरकार ने **वित्तीय प्रोत्साहन, आसान क्रेडिट, PLI योजनाएँ, और अवसंरचना विकास** जैसे उपाय किए।
   - फिर भी, निजी पूंजी को **घरेलू निवेश बढ़ाने, मजदूरी सुधारने और R&D में निवेश** करने की आवश्यकता है।
3. **सामाजिक और समावेशी पूंजीवाद**
   - भारतीय पूंजी को **सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हितों को भी प्राथमिकता** देनी होगी।
   - यह moderate wage growth, रोजगार सृजन और घरेलू खपत के लिए जरूरी है।

निष्कर्ष

वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर में **भारत की विकास रणनीति घरेलू पूंजी पर निर्भर** होनी चाहिए। निजी व्यवसायों को केवल लाभ कमाने के बजाय **देश के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता** देनी होगी, निवेश बढ़ाना होगा, मजदूरी सुधारनी होगी और R&D में योगदान देना होगा। सरकार और भारतीय पूंजी के **सहयोग से ही स्थिर और समावेशी विकास** सुनिश्चित किया जा सकता है।

UPSC Prelims Practice Question

Ques: भारतीय पूंजी और घरेलू निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का निजी क्षेत्र GDP का 0.64% ही R&D में निवेश करता है।

2. भारत में निजी निवेश लगातार बढ़ रहा है, जबकि FDI प्रवाह कम हो रहा है।

3. वैश्विक अस्थिरता के कारण भारत को घरेलू मांग बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

सही विकल्प:

A) केवल 1 और 3 सही है

B) केवल 2 और 3 सही है

C) केवल 1 और 2 सही है

D) सभी 1, 2 और 3 सही हैं

Ans : c)

UPSC Mains Practice Question

Ques: वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारतीय निजी पूंजी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसके योगदान को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। **(150 Words)**

Page : 08 Editorial Analysis

A path to progress that is paved with gold

Atmanirbharta has been central to India's story, not just as an economic plan but also as a philosophy of existence. For us, self-reliance has always meant drawing strength from within so that we may stand taller in the world. Under Prime Minister Narendra Modi, India has embraced Atmanirbharta with renewed vigour, transforming ambitious ideas into tangible national achievements across sectors. His governance has propelled India's self-reliance journey, demonstrating unparalleled resilience and innovation even amid global uncertainties.

This instinct has defined India's journey: when droughts struck in the 1960s, the Green Revolution made India food secure; in the 1990s, foresight in the digital sphere turned talent into national strength; during the COVID-19 pandemic, India developed its own indigenous vaccines rapidly, showcasing scientific and manufacturing self-reliance; today, it is advancing towards self-reliance in defence systems. The lesson remains consistent: whenever India has chosen self-reliance, crisis has been turned into capability.

That principle now needs its strongest expression in financing India's growth. India has drawn over $1 trillion in gross FDI since 2000, yet global realities are shifting. Global investment flows have shrunk by more than 11% in calendar year 2024 while international project finance deals fell by 27%. Foreign portfolio investments, while substantial, remain volatile, swayed by global tremors. As the world retreats from globalisation and the costs of capital rise abroad, India cannot afford to hinge its future on external flows. The time has come to unlock Bharat's own wealth to fuel Bharat's own growth.

A stock of immense value

The most compelling starting point is gold. For generations, gold has been both a store of value and a symbol of security in Indian households. Over time, this trust has expanded to an extraordinary scale: families in India today collectively hold close to 25,000 tonnes of gold, making this the single largest private reserve in the world. At today's prices, this translates to about $2.4 trillion of wealth, or more than 55% of India's GDP in FY26 terms – a stock of value even larger than all the credit extended by India's banks.

Gourav Vallabh

is a Part-Time Member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM) and Professor of Finance

Paradoxically, despite such reserves, India remains one of the largest importers of gold, meeting roughly 87% of demand from abroad, with imports accounting for 8% of its total bill. Between 2010 and 2013, gold imports made up almost a third of India's trade deficit. This paradox highlights both an enormous challenge and an unprecedented opportunity.

Because India's relationship with gold is cultural and civilisational, coercive restrictions are not the answer. What is needed instead is a revitalised, trust-based gold monetisation scheme. Unlike past experiments that faltered due to weak infrastructure and limited outreach, a reimagined scheme must build on global best practices. A striking example comes from a few nations that successfully invested in assaying facilities, created innovative gold savings products, and digitised gold flows through mobile apps, managing to bring thousands of tonnes of "under-the-pillow" gold into their formal financial system. India can adapt these lessons.

A revitalised, trust-based gold monetisation scheme can help India define its growth on its own terms

The basics

The road ahead demands three essentials. First, infrastructure – hallmarking and purity testing centres need to scale faster for trusted valuation across the country. India requires a formal network of collection and purity testing centres. Only recently has it begun expanding the reach of standardised testing: the number of Bureau of Indian Standards-registered assaying and hallmarking centres has almost doubled in the last four years. Yet, a large share of the market still consists of unbranded gold with uncertain purity, which prevents the efficient recycling of gold into the economy. Second, logistics – banks can manage the money flows, while experienced collection and purity testing centres handle gold movement securely and transparently. Third, digitalisation – every household depositor should be able to track their "metal balance" as easily as a bank account balance. But, above all, trust is the foundation. To build it, we must remove frictions such as goods and services tax and customs scrutiny on deposits, and ensure a simple, "no questions asked" environment where returns flow back directly to depositors without hidden costs.

If structured this way, the economics are favourable. The cost of funds raised through gold monetisation could fall in the range of 4.5%-6.5%, lower than the effective cost of borrowing from international markets. Even if a fraction of India's household is mobilised, the impact would be transformative – easing import pressure, strengthening the current account and creating a vast pool of domestic capital to drive infrastructure, manufacturing and innovation.

Moment of financial self-reliance

History shows that India has always risen to moments of crisis, transforming them into capability. Just as it attained food security during the Green Revolution and global leadership in IT services during the digital age, its now stands before the call for financial self-reliance. Mobilising domestic wealth, particularly through gold, is not just an economic choice. It is a civilisational one.

This is about building the confidence that Bharat can fund Bharat, harnessing its own wealth, ingenuity, and resilience. The path forward demands trust, foresight and determination. But the prize is unmistakable – an India that defines its growth on its own terms, self-reliant in spirit and substance, and financing its aspirations from within to step boldly into the future.

The views expressed are personal

GS. Paper 3– Indian Economy

UPSC Mains Practice Question: भारत में मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच घरेलू पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। **(150 Words)**

Context :

आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 1960 के दशक में **हरित क्रांति** ने भारत को खाद्य सुरक्षा दिलाई, 1990 के दशक में **डिजिटल क्रांति** ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाया, और **COVID-19 महामारी** के दौरान देश ने स्वयं के टीके विकसित किए। आज, वैश्विक आर्थिक मंदी, घटती विदेशी निवेश प्रवाह और अस्थिर विदेशी पूंजी के दौर में, भारत के सामने **आर्थिक आत्मनिर्भरता** की चुनौती है।

Static Context

1. **आत्मनिर्भरता और भारत का आर्थिक इतिहास**
   - हरित क्रांति → खाद्य सुरक्षा।
   - आईटी क्रांति → वैश्विक सेवाओं में नेतृत्व।
   - COVID-19 → वैज्ञानिक और विनिर्माण आत्मनिर्भरता।
   - रक्षा उद्योग → रणनीतिक आत्मनिर्भरता।
2. **भारत में स्वर्ण भंडार**
   - भारतीय घरानों के पास **~25,000 टन सोना** है, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग $2.4 ट्रिलियन (~FY26 GDP का 55%) है।
   - इसके बावजूद, भारत **87% सोने की जरूरत** विदेश से आयात करता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता है।
   - सोना न केवल निवेश का माध्यम है, बल्कि **सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य** भी रखता है।

वर्तमान संदर्भ

1. **वैश्विक वित्तीय चुनौतियां**
   - 2024 में वैश्विक FDI प्रवाह में >11% की कमी।
   - अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों में 27% गिरावट।
   - विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर और वैश्विक झटकों से प्रभावित।
2. **गोल्ड मोनेटाइजेशन (GMS) का महत्व**
   - पारंपरिक तरीके से सोना जुटाने के बजाय **विश्वास पर आधारित नई योजना** अपनाना आवश्यक।
   - मुख्य स्तंभ:
     - **इन्फ्रास्ट्रक्चर:** देशभर में हॉलमार्किंग और शुद्धता जाँच केंद्र।
     - **लॉजिस्टिक्स:** सुरक्षित सोने का संकलन और बैंक द्वारा वित्तीय प्रबंधन।
     - **डिजिटलीकरण:** हर परिवार अपने सोने का बैलेंस बैंक खाते की तरह ट्रैक कर सके।
     - **विश्वास:** सरल प्रक्रिया, न्यूनतम कर और पारदर्शी रिटर्न।
   - **आर्थिक लाभ:** सोने से फंड की लागत 4.5–6.5% तक, जो अंतर्राष्ट्रीय उधारी से कम; व्यापार घाटा कम; घरेलू पूंजी सृजन और बुनियादी ढांचा, निर्माण और नवाचार में निवेश।
3. **व्यापक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**
   - घरेलू पूंजी जुटाना सिर्फ आर्थिक विकल्प नहीं, **सांस्कृतिक और नागरिक जिम्मेदारी** भी है।
   - इससे भारत अपनी विकास यात्रा को **आत्मनिर्भर रूप से** संचालित कर सकेगा।

UPSC के लिए मुख्य बिंदु

1. **प्रीलिम्स:**
    - भारत का सोना भंडार और आयात निर्भरता।
    - FDI और FPI प्रवृत्तियां।
    - गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना की विशेषताएँ।
2. **मेनस (GS पेपर 3):**
    - घरेलू संसाधनों के माध्यम से आर्थिक विकास।
    - आत्मनिर्भरता और वित्तीय स्वावलंबन।
    - वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और घरेलू नीतियां।
    - बुनियादी ढांचा, उत्पादन और नवाचार के लिए नवाचारी वित्तीय साधन।

निष्कर्ष

भारत का **गोल्ड-आधारित वित्तीय आत्मनिर्भरता** का रास्ता न केवल आर्थिक बल्कि **सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण** है। घरेलू सोने का सुरक्षित और डिजिटल उपयोग, विश्वसनीय मोनेटाइजेशन, और सरल प्रक्रिया के माध्यम से देश अपने व्यापार घाटे को कम कर सकता है, घरेलू पूंजी बढ़ा सकता है और बुनियादी ढांचे तथा नवाचार में निवेश कर सकता है। जैसे भारत ने हरित क्रांति, डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के माध्यम से संकट को अवसर में बदला, वैसे ही **सोने के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता** भारत के विकास की अगली दिशा तय करेगी।

NITIN SIR CLASSES
NITIN SIR CLASSES
STARING 6TH OCT 2025
PSIR
MENTORSHIP BY-NITIN KUMAR SIR
COMPREHENSIVE COVERAGE (4-5 MONTHS)
DAILY CLASSES : 2 hrs. (ONLINE CLASS)
350+ HRS . MAXIMUM: 40 STUDENTS PER BATCH.
PERIODIC DOUBT SESSION & CLASS TEST
16 SECTIONAL TEST (4 FROM EACH SECTION)
4 FULL LENGTH TEST
CHAPTERWISE PYQS DISCUSSION
CHAPTERWISE COMPILATION OF QUOTATION
DAILY ANSWER WRITING
ONE TIME PAYMENT
RS 25,000/-
PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 30,000/-
www.nitinsirclasses.com
https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR)
99991 54587

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

प्रारम्भ बैच (PT BATCH 2026)

- DURATION : 7 MONTH
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- DAILY THE HINDU ANALYSIS
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES
- DOUBT SESSIONS

ONE TIME PAYMENT
RS 17,500/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 20,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

Daily News Analysis

NITIN SIR CLASSES

NITIN SIR CLASSES

STARING 4TH OCT 2025

आधार बैच (Aadhaar Batch)

- DURATION : 2 YEARS
- DAILY CLASSES : 2 (90 MIN EACH)
- BOOKS – PT ORIENTED PYQ'S + MAINS
- MAGZINE : HARD + SOFT COPY
- NCERT FOUNDATION
- SEPERATE PT & MAINS QUESTION SOLVING CLASSES
- TEST SERIES WITH DISCUSSION
- MENTORSHIP (PERSONALISED)
- BILINGUAL CLASSES & DOUBT SESSIONS
- MAINS ANSWER WRITING CLASSES

ONE TIME PAYMENT
RS 50,000/-

PAY IN 2 EASY INSTALMENTS
RS 55,000/-

Register Now https://t.me/NITIN KUMAR (PSIR) 99991 54587

NITIN SIR CLASSES
Nitin sir classes
Know your daily
CLASSES
TIME TABLE FOR DAILY CLASSES
• 07:30 PM - THE HINDU ANALYSIS
• 09:00 PM - Daily Q & A Session (PT + Mains)
SUBSCRIBE
HTTPS://T.ME/NITIN KUMAR (PSIR)
WWW.NITINSIRCLASSES.COM

Daily News Analysis

Follow More

- **Phone Number : - 9999154587**
- **Website : - https://nitinsirclasses.com/**
- **Email : - k.nitinca@gmail.com**
- **Youtube : -https://youtube.com/@nitinsirclasses8314?si=a7Wf6zaTC5Px08Nf**
- **Instagram :- https://www.instagram.com/k.nitinca?igsh=MTVxeXgxNGJyajN3aw==**
- **Facebook : - https://www.facebook.com/share/19JbpGvTgM/?mibextid=qi2Omg**
- **Telegram : - https://t.me/+ebUFssPR83NhNmJl**